हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 2 अगस्त 2024, समय 1810 (10 मिनट))

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की अध्यक्षता में दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ ।
- शंभू बॉर्डर को खुलवाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई- बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश, 12 अगस्त को फिर होगी सुनवाई।
- विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल से मुलाकात कर बोगस वोटर्स मामले में विशेष सर्वेक्षण की मांग की।
- पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर स्वदेश लौटे शूटर सरबजोत सिंह का अंबाला पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, कहा-प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन से कर पाया बेहतर प्रदर्शन।
- प्रदेश भर में सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की अध्यक्षता में दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में शुरु हो गया है। यह राष्ट्रपति के संचालन में राज्यपालों का पहला सम्मेलन है और सभी राज्यों के राज्यपाल इस बैठक में भाग ले रहे हैं। उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तथा केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेन्द्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय में मंत्रिमंडलीय सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। बैठक की कार्यसूची में तीन आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और विभिन्न खंडों या सीमावर्ती इलाकों जैसे ध्यान देने वाले क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा **माई भारत**, **एक भारत श्रेष्ठ भारत** और **एक वृक्ष मां के नाम** तथा **प्राकृतिक खेती** जैसे कई अभियानों में राज्यपालों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यपालों की भूमिका और राज्यों में विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श होगा। राज्यपाल विभिन्न अलग-अलग समूहों में इन विषयों पर बातचीत करेंगे। समापन सत्र में ये समूह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिभागियों के समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे।

पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच शंभू बॉर्डर बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा और पंजाब सरकार ऐसे निष्पक्ष लोगों के नाम पर विचार करे जो किसानों से बात कर सके और परेशानी का हल निकाले।वहीं, शंभू बॉर्डर को आम गाड़ियों के लिए खोले जाने की पंजाब सरकार के वकील की मांग पर हरियाणा सरकार षार मेहता ने कहा कि धरना दे रहे किसान खुद अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रख रहे।

मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखते हुए शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा।गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर को किसानों ने पिछले 6 महीनों से बंद कर रखा है, जिस कारण अंबाला के व्यापारियों को प्रतिदिन लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने आज चंडीगढ़ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल से मुलाकात कर मतदाता सूचियों और मतदान प्रक्रिया में व्याप्त खामियों को दूर करने की मांग की। इस संबंध में विस अध्यक्ष ने 27 जुलाई को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे गए पत्र की प्रति और मतदाता सूचियों की त्रुटियां दर्शाने वाले सर्वे दस्तावेज सुपुर्द किए। इस दौरान उन्होंने इन त्रुटियों को लेकर विस्तार से बात भी की।उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में मृतकों और निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर जा चुके व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। कुछ मतदाताओं के वोट एक से अधिक स्थानों पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश जारी कर मतदाता सूचियों को अपडेट करवाना चाहिए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंचायतों को 21 लाख रुपये तक के काम अपने स्तर पर करवाने के किए गए वायदे को पूरा किया है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायतों को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करते हुए उन्हें स्टेट फंड से भी 21 लाख रुपये तक के काम करवाने की मंजूरी प्रदान की है।विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है, जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों को विकास कार्यों के निष्पादन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय से स्थानीय सरकारों को और मजबूती मिलेगी साथ ही गांवों में विकास कार्य भी तेज गति से हो सकेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने पहले ही पंचायतों को उनके पास उपलब्ध कुल ग्राम निधि या समिति निधि या जिला परिषद निधि में से बिना टेंडर प्रक्रिया के 21 लाख रुपये तक की अनुमानित लागत के विकास कार्य करवाने की अनुमति दे रखी है। अब स्टेट फंड से भी अतिरिक्त कार्य करवाने के निर्णय से विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी

पेरिस ओलंपिक 10 मीटर शूटिंग में कांस्य पदक जीतने के बाद आज सरबजोत सिंह अंबाला स्थित अपने पैतृक गांव धीन में पहुंचने पर ढ़ोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। सरबजोत ने कहा कि उन्हें कांस्य पदक जितने पर काफी खुशी है लेकिन अगले ओलंपिक में वे पदक का रंग बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने माता-पिता व अपने कोच को देते हुए कहा कि मुझे इस बार ओलंपिक में बहुत कुछ सिखने को मिला है। सरबजोत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन से उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।

प्रदेश भर में आज विभिन्न मंदिरों में कवड़िओं ने हरिद्वार से कांवड़ लाकर जलाभिषेक किया। कैथल स्थित महाभारत कालीन प्राचीन ग्यारह रुद्री मंदिर में जलाभिषेक हुआ। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए लाइनों में लगे । हिसार में भी शिवरात्रि का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली । हरिद्वार से कांवड़ लेकर हिसार पहुंचे कांवड़ियों ने बताया कि मन की इच्छा पूर्ण होने पर कांवड़ लेकर आए हैं। रास्ते में कांवड़ियों की सुरक्षा व खाने-पीने का विशेष इंतजाम किया गया था।

आज श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर फरीदाबाद के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने सेक्टर-62 स्थित मंदिर पहुंचकर स्थानीय निवासियों को बधाई दी और कावड़ लेकर आए सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं दीं। इसके बाद, \"एक पेड़ मां के नाम, दूसरा पेड़ पूर्वजों के नाम\" अभियान का शुभारंभ किया गया।

कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए हम सभी को जागरूक रहना होगा। महाशिवरात्रि का पर्व पलवल जिले में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिवरात्रि के अवसर पर पलवल के पंचवटी मंदिर पर शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंदिर में सेवादल द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। छोटी काशी भिवानी में शिवरात्रि पर शनिवार को सुबह से मदिरों में शिवभक्तों की भारी भीड़ देखी गई।बम-बम भोले के जयकारे लगाते हुए शिव भक्तों ने श्रद्धा एवं उल्लास से यह पर्व मनाया। शिवभक्तों द्वारा शिव का जलाभिषेक किया गया एवं शिवभक्तों द्वारा हरिद्वार से लाई गई कांवड़ें भी चढ़ाई गई। श्रद्धालुओं ने देश मे अमन चैन व शांति की मुरादें मांगी व पर्यावरण संरक्षण व जल बचाने की अपील भी की।

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि शहरी निकायों के किरायेदारों, लीजधारकों, तहबाजारी वालों के लिए सम्पत्ति के स्वामित्व का दावा प्रस्तुत करने की आखरी समय-सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।उन्होंने बताया कि अभी तक मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 5962 आवेदन स्वीकृत हुए हैं तथा 5026 की रजिस्ट्री भी करवा दी गई है।श्री सुधा ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत पहले 31 दिसंबर 2020 को वह दुकानदार ही आवेदन कर सकते थे जिन को 20 वर्ष या इससे अधिक का समय किराया,लीज,तहबाजारी पर काबिज़ हुए पूरा हो चुका है। परंतु अब जनता के अनुरोध पर मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी ने आवेदन करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका के किराए, लीज, तहबाजारी वाली दुकान, मकान पर काबिज हुए किसी व्यक्ति को इस

वर्ष 31 अक्तूबर तक 20 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया है, तो अब वह भी पोर्टल पर आवेदन कर सकता है ।

हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना-2024 शुरू की गई है। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे घरेलू उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनके बिजली बिल 31 दिसम्बर,2023 तक बकाया थे तथा अब तक बकाया हैं। यह योजना कनेक्टिड और डिस्कनेक्टिड दोनों तरह के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है।उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण घरेलू बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त या अगले 3 मासिक /द्विमासिक बिलों के साथ किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।उन्होंने बताया कि फ्रीज किया गया सरचार्ज निर्धारित किस्तों तथा आगामी 3 मासिक /द्विमासिक बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता निर्धारित किस्तें और आगामी 3 मासिक /द्विमासिक बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर समझा जाएगा।
हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने और अपग्रेड करने के लिए नवीनतम उपकरणों की खरीद पर 2 करोड़ 64 लाख 77 हजार 224 रुपए की राशि खर्च की जाएगी ताकि प्रदेश में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न प्रकार के उपकरणों की खरीद के लिए पुलिस विभाग की हरियाणा राज्य डिसास्टर रिस्पोंस फोर्स की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। यह कमेटी आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध उपकरणों की जांच एवं आपदा के दौरान कार्य करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य करेगी। इसके अलावा फायर सेफटी मॉक ड्रिल के साथ हरियाणा सिविल सचिवालय एवं राज्य के लघु सचिवालयों में फायर सेफटी ऑडिट कार्य करेगी।

अतिरिक्त उपायुक्त सचिन गुप्ता ने वीरवार को सेक्टर-5 पंहुचकर 4 अगस्त को आयोजित होने वाले राहगीरी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को सेक्टर-5 में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की विशेष उपस्थिति रहेंगे।उन्होंने कहा कि हरियाणा का प्रसिद्ध राहगीरी कार्यक्रम एक बार फिर से पंचकूला में आयोजित होने जा रहा है, जिससे पंचकूलावासियों में भारी उत्साह है। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्यक्रम में हर वर्ग के लोगों की

अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होनंे बताया कि राहगीरी कार्यक्रम के दौरान, बच्चों और वयस्कों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग-अलग गतिविधि आयोजित की जाएगी, जिसमें साइकिलिंग, स्केटिंग, दौड़ और पैदल चलना जैसी विभिन्न शारीरिक गतिविधियों शामिल है।

वसतु और सेवा कर- जीएसटी राजसव संग्रह में दस दशमलव तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जुलाई में जीएसटी संग्रह एक लाख 82 हजार करोड रूपये से अधिक हो गया। यह अब तक का तीसरा सबसे अधिक राजसव संग्रह है। वितत मंत्रालय के आंकडों के अनुसार जुलाई में जीएसटी संग्रह रिफंड समायोजित करने के बाद लगभग एक लाख 60 हजार करोड रूपये रहा, जो 14 दशमलव चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। वितत मंत्रालय ने बताया कि वसतु और सेवाओं में घरेलू लेनदेन ब□ने के कारण जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई।